जनसंख्या की खबर का सच

संपादन

वरुण शैलेश

संजय कुमार बलौदिया

मीडिया स्टडीज ग्रुप

दिल्ली-110085

MSG BOOKS
प्रथम संस्करण : 2016

www.mediastudiesgroup.org.in

संपादन
वरुण शैलेश
संजय कुमार बलौदिया

ISBN : 978-93-84304-08-9

मूल्य : ₹ 125

JANSANKHYA KI KHABAR KA SACH
Edited by
Varun Shailesh
Sanjay Kumar Balaudia

प्रकाशक
मीडिया स्टडीज ग्रुप
ए-4/5, सेक्टर-18, रोहिणी
दिल्ली-110085

मुद्रक
डॉल्फिन प्रिंटो ग्राफिक्स, 4-ई/7, पाब्ला बिल्डिंग,
झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अनुक्रम

उर्दू अखबारों में जनगणना की प्रस्तुति

अभय कुमार

अंग्रेजी के एक तबके सहित हिन्दी अखबारों के बड़े हिस्से में धार्मिक आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के कारण हिन्दू खत्म हो जाएंगे। इसके उलट उर्दू के अखबारों के प्रस्तुतिकरण में एक संतुलन दिखता है। पहली बात कि उर्दू अखबारों ने मुस्लिम बहुलता के डर को खारिज कर दिया। दूसरे, उन्होंने बिहार चुनाव से पहले भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक आंकड़ों को जारी करने के 'समय' पर सवाल खड़ा किया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2015 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। अध्ययन के लिए इस पर्चे में उर्दू के तीन अखबारों 'रोजनामा राष्ट्रीय सहारा', 'इंकलाब' और 'सहाफत' को शामिल किया गया है।

हिन्दी अखबारों के मुकाबले उर्दू के समाचार पत्रों ने 26 अगस्त 2015 को धार्मिक आंकड़ों पर गंभीर एवं संतुलित रिपोर्टें प्रकाशित की। 'रोजनामा राष्ट्रीय सहारा' ने इस समाचार को पहले पेज पर प्रमुख खबर के तौर पर प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक है 'मुसलमान की आबादी 14.2 फीसद'[1]। इसी तरह 'इंकलाब' ने सीधी हेडिंग रखी और लिखा, 'मरकज ने मजहबी बुनियाद पर कराई गई मरदम शुमारी के नतीजे जारी किए'[2] यानी सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के नतीजे जारी किए। हालांकि 'सहाफत' सनसनीखेज खबरों की प्रस्तुतिकरण की दौड़ में शामिल होने से खुद को नहीं रोक सका। 'सहाफत' ने पहले पन्ने पर 'मुसलमान के मुकाबले कम हुए हिन्दू'[3] शीर्षक से प्रमुख खबर को प्रकाशित किया। इसका एक कारण यह हो सकता है कि अन्य छोटे अखबारों की तरह 'सहाफत' भी तेजी से अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए खबरों के सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण का रास्ता

अख्तियार कर रहा हो। सामग्री में सुधार के बजाय 'सहाफत' जैसे अखबार पूरे मुद्दे को सनसनीखेज बनाने में जुटे रहते हैं।

'इंकलाब' और 'सहाफत' के विपरीत रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने धार्मिक आंकड़ों के जारी होने के एक दिन बाद इस मुद्दे पर संपादकीय छापा जिसका शीर्षक था 'हंगामा क्यों है बरपा' सहारा ने सलीके से हिन्दू आबादी घटने पर टिप्पणी की। सहारा लिखता है कि जानबूझकर मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात कही जा रही है। वहीं 2001-2011 के दौरान मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 29 फीसदी से घटकर 24.6 फीसदी पर पहुंच गई है मगर इस बिन्दु को गौण करने की सचेत कोशिश दिखती है। संपादकीय में मुस्लिम आबादी की विकास दर बढ़ने की बात को खारिज करते हुए उसे बेबुनियाद बताया गया है।

संपादकीय में लिखा गया है कि दक्षिणपंथी खेमे द्वारा यह वहम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम तेजी से बढ़ रहे हैं जो चार-चार शादियां करते हैं और इससे हिन्दू जल्द ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों की दशकीय वृद्धि दर में भारी कमी आई है। मसलन 1951 में मुस्लिम आबादी 34.4 फीसदी थी जो 2011 में घटकर 24.6 फीसदी रह गई है। संपादकीय में लिखा गया है कि यह प्रचारित किया जाता है कि 266 वर्षों में आबादी के मामले में मुस्लिम हिन्दुओं को पछाड़ देंगे जबकि यह कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा; दुनिया रहेगी या नहीं। दूसरे, 96.33 करोड़ हिन्दुओं को 17.2 करोड़ मुस्लिमों से क्या खतरा हो सकता है? इसलिए बहुमत की आबादी को मुस्लिमों से डरने की जरूरत नहीं है। मजेदार बात यह है कि संपादकीय में हिन्दुओं में सिखों, जैनियों और बौद्धों की आबादी को जोड़ दिया गया है, जो एक अरब तक पहुंच जाते हैं। सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और पारसी अधिसूचित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय हैं। संपादकीय में दक्षिणपंथियों की आलोचना के साथ ही यह भी लिखा गया है कि देश में उनके निशाने पर मुस्लिम और ईसाई ही होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सहारा के इस संपादकीय में सिखों, जैनियों और बौद्धों को 'वृहद हिन्दू परिवार' का सदस्य माना गया है।

इसके बाद संपादकीय में दूसरे समुदायों की तुलना में मुस्लिमों में ज्यादा बच्चे पैदा करने को देश के लिए खतरा बताने पर टिप्पणी की गई है। संपादकीय में लिखा गया कि हिन्दू-मुस्लिम तुलना की विधि ही गलत है क्योंकि दोनों समुदायों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर एक ही तराजू में नहीं

तौला जा सकता है। दोनों भिन्न हैं। इसके बजाय सभी धर्मों की कमजोर जातियों और वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। मसलन हिन्दू सवर्ण जातियों में कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति देखी जाती है ताकि जायदाद में ज्यादा बंटवारा न करना पड़े। यही बात मुस्लिमों की कथित उच्च जातियों में भी देखी जाती है। लेकिन सभी धर्मों के गरीबों और अशिक्षित लोगों में अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का चलन है। संपादकीय में हिन्दुओं की आबादी घटने पर चर्चा के दौरान सवाल करते हुए कहा गया है कि धार्मिक आंकड़ों को प्रकाशित करते वक्त सरकार को व्यावहारिक होना चाहिए। उर्दू अखबारों में जनसंख्या के आंकड़ों को जारी करने के समय को लेकर सरकार की मंशा के पीछे एक चिंता दिखती है। सहारा के संपादकीय[4] में लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने को लालायित भाजपा ने जानबूझकर चुनाव से ऐन पहले यह आंकड़ा जारी किया है। ताकि सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। सहारा ने प्रमुख विपक्षी नेताओं के बयान प्रकाशित किए। सहारा ने जदयू नेता सईद मोहम्मद अशरफ की टिप्पणी प्रकाशित की जिसका शीर्षक 'मजहब पर मबानी मरदम शुमारी रिपोर्ट की पेशकश गलत'[5] था। अशरफ ने कहा, भाजपा को बिहार चुनाव से पहले जनसंख्या के आंकड़ों को जारी कर समाज को सांप्रदायिक तौर पर बांटने से बचना चाहिए। उसे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन आंकड़ों को जारी कर हिन्दू-मुस्लिम एकता को कमजोर करना चाहती है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है।

इसी तरह इंकलाब[6] ने जदयू नेता केसी त्यागी के बयान को छापा। सरकार के धार्मिक आंकड़ों को जारी करने के कदम का विरोध करते हुए त्यागी ने कहा कि केंद्र को धर्म आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी करने की बजाय जाति आधारित आंकड़ों को जारी करना चाहिए। अशरफ की तरह ही त्यागी ने भी इस बात को दोहराया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धर्म आधारित आंकड़ों को जारी करना धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास है। इंकलाब[7] ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता रीता बहुगुणा की टिप्पणी छापी। बहुगुणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने धार्मिक आंकड़ों को जारी करते हुए प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। जारी करने से पहले जनगणना के आंकड़ों को संसद में पेश करना होता है। उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की इस कोशिश पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

विपक्षी दलों की चिंताएं निराधार नहीं हैं, जबकि यह भी तथ्य है वे, खासकर कांग्रेस भी अतीत में राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की रिपोर्टों का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन जब मुसलमानों पर हिंदू दक्षिणपंथियों के हमले तेज हो गए हैं, वैसी स्थिति में उर्दू प्रेस इन आवाजों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता।

संदर्भ सूची

1. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 26 अगस्त 2015, पेज 1
2. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 27 अगस्त 2015, पेज 7
3. सहाफत, नई दिल्ली, 26 अगस्त 2015, पेज 1
4. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 26 अगस्त 2015, पेज 7
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 26 अगस्त 2015, पेज 6
6. इंकलाब, नई दिल्ली, 27 अगस्त 2015, पेज 9
7. इंकलाब, नई दिल्ली, 29 अगस्त 2015, पेज 5